बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 76 ● नई दिल्ली ● बुधवार 31 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

5 जनवरी से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा सत्र, इन मुख्य मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। दिल्ली में 5 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। यह तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र होगा। सत्र के दौरान पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के पुनर्निर्माण से जुड़ी इस रिपोर्ट को लेकर होगी, जिसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसकी पुष्टि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने की है। इस रिपोर्ट में 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले (जिसे भाजपा ने शीश महल का नाम दिया है) के नवीनीकरण में हुए खर्च और कथित वित्तीय अनियमितताओं का लेखा-जोखा होने की संभावना है। इसके अलावा सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने संकेत दिए हैं कि वे न केवल शीश महल बल्कि दिल्ली जल बोर्ड और मोहल्ला क्लीनिक से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट भी पेश कर सकते हैं।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा के निधन पर राहुल गांधी ने जताया शोक, किया भावुक पोस्ट

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का मंगलवार सुबह निधन हो गया। उनके निधन की खबर से बांग्लादेश सहित पूरे क्षेत्र की राजनीति में शोक की लहर फैल गई है। वरिष्ठ राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता और आम नागरिक उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन से वे अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में बांग्लादेश की राजनीतिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने उनके परिवार, समर्थकों और बांग्लादेश के लोगों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं प्रकट कीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर जारी अपने संदेश में कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से वे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देश की राजनीति को दिशा देने में अहम

भूमिका निभाई। खड़गे ने उनके परिवार, समर्थकों और बांग्लादेश के नागरिकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की ओर से जारी बयान के अनुसार, बेगम खालिदा जिया का मंगलवार सुबह करीब छह बजे निधन हुआ। उन्होंने ढाका स्थित एवरकेयर अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया गया है कि वे पिछले एक महीने से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थीं और उनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा था। पार्टी की ओर से यह भी बताया गया कि फज्र की नमाज के तुरंत बाद उनका इंतकाल हुआ। खालिदा जिया के निधन की खबर सामने आते ही बांग्लादेश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई।

पार्टी कार्यालयों और समर्थकों के बीच गहरा दुख देखा गया, वहीं कई राजनीतिक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकारी के अनुसार, 23 नवंबर को दिल और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर समस्याओं के चलते उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इसके बाद से उनकी सेहत में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहा। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंतिम दिनों में वे निमोनिया से भी पीड़ित थीं और करीब 36 दिनों तक डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रहीं। इस दौरान उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही थी। पिछले कुछ वर्षों से बेगम खालिदा जिया कई पुरानी बीमारियों से जूझ रही थीं। उनके उपचार के लिए एक विशेष मेडिकल टीम गठित की गई थी, जिसमें बांग्लादेश के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल थे। सभी डॉक्टर मिलकर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए थे। इस महीने उन्हें बेहतर इलाज के लिए विदेश ले जाने की संभावना पर भी विचार किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद इस योजना को रद्द कर दिया गया। चिकित्सकों का कहना था कि उनकी तबीयत अत्यंत कमजोर थी और वे अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने की स्थिति में नहीं थीं। बेगम खालिदा जिया के निधन को बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। उनके लंबे राजनीतिक जीवन और योगदान को देश हमेशा याद रखेगा।

प्रियंका राजस्थान पहुंचीं : रेहान के साथ सवाई माधोपुर आया गांधी-वाड्रा परिवार, अवीवा के भी साथ होने की अटकलें

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा अपने परिवार के साथ आज सवाई माधोपुर पहुंचे। गांधी-वाड्रा परिवार का काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली से सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर आया। यह यात्रा पूरी तरह निजी बताई जा रही है। परिवार ने रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग में ठहरने की व्यवस्था की है। सूत्रों के अनुसार, गांधी-वाड्रा परिवार 2 जनवरी तक रणथंभौर में रहेगा। इस दौरान परिवार रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने का भी कार्यक्रम करेगा। परिवार के साथ उनके कुछ करीबी दोस्त भी मौजूद हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई दिल्ली निवासी अवीवा बेग से हो चुकी है। ऐसे में गांधी-वाड्रा परिवार के साथ अवीवा बेग के परिवार के भी रणथंभौर पहुंचने की अटकलें हैं। बताया जा रहा है कि तीनों परिवार मिलकर रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगे।

जानकारी के मुताबिक, रेहान पेशे से फोटोग्राफर हैं और अवीवा बेग भी फोटोग्राफर हैं। दोनों परिवारों की सहमति के बाद दिल्ली में एक बेहद निजी समारोह में रेहान और अवीवा की सगाई संपन्न हुई। गांधी-वाड्रा परिवार का रणथंभौर से पुराना और गहरा जुड़ाव रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा अक्सर रणथंभौर आती रहती हैं, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी कई बार यहां आ चुके हैं। प्रियंका का परिवार साल में दो से तीन बार रणथंभौर आता है और नेशनल पार्क में बाघों की अठखेलियां देखने का आनंद लेता है। इस बार भी गांधी-वाड्रा परिवार रणथंभौर पहुंचा है और यहां भ्रमण के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी है। हालांकि इस बार सोनिया गांधी परिवार के साथ नहीं आईं। बताया जा रहा है कि रेहान और अवीवा की सगाई से जुड़ी कुछ रस्में होटल शेरबाग में हो सकती हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

रेहान और अवीवा की हुई सगाई

सूत्रों के अनुसार, दोनों परिवारों के बीच सगाई का कार्यक्रम पहले ही हो चुका है। सगाई कार्यक्रम में चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया और इसे काफी निजी रखा गया। रेहान और अवीवा कई वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं।

रेहान वाड्रा हैं विजुअल आर्टिस्ट

रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। उन्होंने अलग-अलग शहरों में अपने आर्टवर्क की प्रदर्शनी भी लगाई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई लंदन से पूरी की।

अवीवा बेग कौन हैं?

अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी की। अवीवा पेशे से फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं और नेशनल लेवल की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं।

दिल्ली नगर निगम की वित्तीय भविष्य की तैयारी- 25-27 बजट के लिए प्रस्तावों पर काम तेज, राजस्व बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के संशोधित बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में स्थायी समिति की एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए। एमसीडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सिटी-सदर, पहाड़गंज, पश्चिम, मध्य, केशवपुरम, सिविल लाइंस, रोहिणी, करोल बाग, दक्षिण, नजफगढ़, शाहदरा उत्तर, शाहदरा दक्षिण और नरेला क्षेत्रों ने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्य शर्मा ने कहा कि जनहितैषी और व्यावहारिक बजट तैयार करने के लिए सभी क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बजट केवल आय और व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि शहर के विकास को दिशा देने और नागरिकों की अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने का एक मार्गदर्शक है। उन्होंने आगे कहा कि आय और व्यय के बीच असंतुलन को दूर करने के लिए, विभिन्न माध्यमों से राजस्व बढ़ाते हुए वित्तीय घाटे को कम करना आवश्यक है, ताकि निगम पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जा सकें। क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्षों ने विभिन्न सुझाव दिए और विशेष रूप से दो प्रमुख पहलुओं पर जोर दिया - अतिरिक्त राजस्व स्रोतों की खोज और विस्तार तथा व्यय में पारदर्शिता। बैठक के दौरान, क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष ने निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई संभावित स्रोतों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें सामुदायिक केंद्रों का अधिकतम उपयोग और कर के दायरे में लाने के लिए नई आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की पहचान करना शामिल है।

आप को भ्रष्टाचारियों से इतना प्रेम क्यों है? दिल्ली के गृह मंत्री का हमला- सबूत दें या मांगें माफी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर आम आदमी पार्टी (आप) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के दस महीने बाद भी आप पार्टी हार नहीं पचा पाई है और लगातार इंटरनेट मीडिया के जरिए झूठ और दुष्प्रचार फैला रही है। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने के लिए पूरे दिन योजनाबद्ध कैंपेन चलाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाया गया कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती के काम में लगाया गया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई सर्कुलर या आदेश मौजूद है, तो आम आदमी पार्टी उसे सार्वजनिक करे, अन्यथा जनता से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि तहसीलदार और सब-इंस्पेक्टर के सस्पेंशन के मामलों में भी प्रशासन के खिलाफ गलत नैरेटिव फैलाया गया। जब भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी नजर आती है। आशीष सूद ने सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारियों से इतना प्रेम क्यों है? उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। मंत्री ने 25 तारीख को फैलाए गए एक और कथित झूठ का जिक्र करते हुए कहा कि यह अफवाह उड़ाई गई कि सांता क्लॉज बनकर आने वाले बच्चों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा कोई आदेश था तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा छुस्सककी आयु-सीमा बढ़ाने को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया। मंत्री ने कहा कि छुस्सक दिल्ली सरकार के अधीन आता है और भर्ती उसकी जिम्मेदारी है, बावजूद इसके केंद्र सरकार का बहाना बनाकर जनता को गुमराह किया गया। प्रेसवार्ता के अंत में मंत्री आशीष सूद ने फिर दोहराया कि अगर शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने का कोई आदेश है, तो आम आदमी पार्टी उसे सार्वजनिक करे, अन्यथा झूठ फैलाने के लिए माफी मांगे।

घने कोहरे से फ्लाइट्स की रफ्तार पर ब्रेक, 118 उड़ानें रद्द; कई डायवर्ट

नई दिल्ली।

देशभर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे ने भी लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। मंगलवार को भी दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली एअरपोर्ट पर सुबह से अभी तक 60 आने वाली फ्लाइट्स, 58 जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल और 16 के रास्ते बदलने की खबर है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मंगलवार सुबह 7 बजे पैसेंजर एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि शहर में पहले घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन विजिबिलिटी में सुधार के बाद फ्लाइट ऑपरेशन आसानी से चल रहे हैं।

एयरपोर्ट ने यात्रियों को भरोसा दिलाया कि यात्रियों की मदद करने और जरूरी सपोर्ट देने के लिए सभी टर्मिनल पर ऑन-ग्राउंड अधिकारी मौजूद हैं। उधर, सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे फ्लाइट्स का स्टेटस पहले से चेक करें, अपनी एअरलाइन के संपर्क में रहें और यात्रा के लिए ज्यादा समय दें। एयरलाइंस को यात्री सुविधा के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें समय पर फ्लाइट्स की जानकारी, देर से आने वाले यात्रियों के लिए खाना, कैंसलेशन होने पर रीबुकिंग या रिफंड, समय पर चेक-इन के बाद बोर्डिंग से मना न करना, बैगेज की सुविधा और शिकायत का तुरंत समाधान शामिल है। सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह तैयार है, और स्थिति पर करीब से नजर रखा जा रहा है।

पंजाब विधानसभा में वीबी-जी राम जी' कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाना संविधान के विरुद्ध : शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली।

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी 'वीबी-जी राम जी' कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाने को संविधान और संघीय ढांचे की मूल भावना के विरुद्ध करार दिया और कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को मानना राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। राजधानी भोपाल स्थित अपने आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह कल्पना लोक में रहते हैं और देश की हकीकत से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, बिना मंत्री परिषद और कैबिनेट के काम चलने की बात कहना केवल भ्रम फैलाना है।

मन में जो आया, वह कह देना जिम्मेदार राजनीति नहीं है। ज्ञात हो कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल से पूछे बिना और मामले का अध्ययन किए बिना अकेले ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म कर दिया। चौहान ने पंजाब विधानसभा में इस विधेयक के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि ये अंध विरोध की राजनीति है और कुछ लोग केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, जिसका लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, अगर संसद में कोई कानून बनता है तो विधानसभा में

उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना हमारे संवैधानिक ढांचे की भावना के खिलाफ है।

केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाया कि क्या यह उचित होगा कि राज्य के कानून के खिलाफ जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करने लगें? उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद द्वारा पारित कानूनों को मानना केंद्र और सभी राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार और विधानसभा में कुछ दल जो कर रहे हैं, वह अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। चौहान ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में मनरेगा सहित कई योजनाओं में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामलेसामने आए हैं लेकिन न तो दोषियों पर कार्रवाई की गई और न ही गबन की गई राशि की वसूली हुई। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में 13 हजार 304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5 हजार 915 में ही सोशल ऑडिट हुआ है। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में करीब 10 हजार 653 वित्तीय गबन के मामले सामने आए, लेकिन इनमें किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मनरेगा में जिन गतिविधियों की अनुमति ही नहीं थीं उन पर भी अनियमित खर्च किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें मजदूरी तक नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए काम नहीं किया जाता, पकड़े जाने पर भी कार्रवाई नहीं होती, और दूसरी तरफ विधानसभा में संसद के कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात होती है। यह अलोकतांत्रिक सोच है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में जी राम जी कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया और भाजपा नीत केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान चर्चा के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया। सोंड ने कहा कि यह अधिनियम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, अनुसूचित जाति समुदायों और ग्रामीण मजदूरों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा जो जीवित रहने के लिए मनरेगा पर निर्भर हैं।

भारत की लोकतांत्रिक चेतना,नागरिक आचरण और मौलिक कर्तव्यों की वैश्विक कसौटी

वैश्विक स्तरपर इकीसवीं सदी का भारत तेजी से आगे बढ़ता हुआ है।डिजिटल इंडिया,स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन,वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, हाईवे ,मेट्रो,ऑनलाइन सेवाएँ और वैश्विक स्तर की बुनियादी सुविधाएँ,ये सभी हमारीसामूहिक आकांक्षाओं का हिस्सा बन चुकी हैं।हम चाहते हैं कि भारत भी उन देशों की श्रेणी में खड़ा हो जहाँ जीवन-स्तर,सार्वजनिक सुविधाएँ और शहरी सौंदर्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों। परंतु इसी के साथ एक मूल प्रश्न लगातार हमारे सामने खड़ा होता है,क्या हम स्वयं वर्ल्ड क्लास नागरिक बनने के लिए तैयार हैं? क्या केवल सरकारों, नीतियों और बजट से कोई देश महान बनता है,या फिर नागरिकों के आचरण,नैतिकता और जिम्मेदारी से राष्ट्र की असली पहचान गढ़ी जाती है? मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारतीय नागरिक आज अपनेअधिकारों के प्रति पहले से कहीं अधिक जागरूक है।सूचना का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा,उपभोक्ता अधिकार, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से सीधे संवाद, इन सबने नागरिक को सशक्त बनाया है।हमअपेक्षा करते हैं कि सड़कें साफ़ हों,पार्क सुंदर हों,स्मारक सुरक्षित हों, सार्वजनिक संपत्ति सुव्यवस्थित हो और शासन पारदर्शी हो। यह अपेक्षा पूरी तरह वैध है,क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक का अधिकार सर्वोपरि है।परंतु अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन क्यों टूट रहा है?यहीं से समस्या की जड़ शुरू होती है। हम अधिकारों की भाषा तो बड़े आत्मविश्वास से बोलते हैं,परंतु मौलिक कर्तव्यों की बात आते ही चुप्पी साध लेते हैं।भारतीय संविधान ने नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि अनुच्छेद 51(क) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखकिया है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना,भाईचारे की भावना विकसित करना और संविधान के मूल्यों का सम्मान करना दुर्भाग्य से,ये कर्तव्य अक्सर किताबों तक सीमित रह जाते हैं। साथियों बात अगर हम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ की घटना- एक छोटी चोरी,एक बड़ा सामाजिक आईना इसको समझने की करें तो,हाल ही में लखनऊ में घटित घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया।यह प्रेरणा स्थल, जहाँ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसी महान विभूतियों की प्रतिमाएँ स्थापित हैं,उसे सुंदर बनाने के लिए लगाए गए फूलों के गमलों की चोरी शुरू हो गई। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। यह घटना इसलिए अधिक चिंताजनक बन जाती है क्योंकि चोरी करने वाले लोग किसी झुग्गी या अत्यंत गरीब पृष्ठभूमि से नहीं थे। वे स्कूटर और कार से आए, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, महिलाएँ और पुरुष हँसते हुए गमले उठाकर ले जा रहे थे। 80-100 रुपये के गमले और करोड़ों की मानसिक दरिद्रता, यहीं प्रश्न केवल 80 या 100 रुपये के गमलों का नहीं है। प्रश्न उस मानसिकता का है जो सार्वजनिक संपत्ति को सरकारी समझकर लूट का माल मान लेती है। जिन लोगों के पास वाहन है, रोजगार है,सामाजिक प्रतिष्ठा है,वे यदि सार्वजनिक स्थल से चोरी करते हुए कोई अपराध- बोध महसूस नहीं करते,तो यह केवल कानून- व्यवस्था की नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता की विफलता है। साथियों बात कर हम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर हँसी के साथ चोरी-संवेदनहीनता का सबसे खतरनाक रूप इसको समझने की करें तो, सबसे दुखद पहलू यह था कि चोरी करते समय उनके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। वे हँस रहे थे, जैसे यह कोई सामान्य या हास्यास्पद काम हो। यह हँसी दरअसल उस सामूहिक संवेदनहीनता का प्रतीक है,जो धीरे-धीरे समाज में गहराई तक पैठ बना रही है।जब गलत कार्य करते समय अपराध-बोध समाप्त हो जाए,तब समाज का नैतिक पतन शुरू हो जाता है। साथियों बात अगर हम गरीब बनाम संपन्नकानून की दोहरी धारणा इसको समझने की करें तो,यह भी एक कटु सत्य है कि यदि कोई गरीब व्यक्ति छोटी सी चोरी करता है,तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाती है। मीडिया ट्रायल, पुलिसिया कार्रवाई और सामाजिक तिरस्कार, सब कुछ उसके हिस्से आता है।परंतु जब अच्छे घरों के लोग,तथाकथित सभ्य समाज के सदस्य ऐसा करते हैं, तो अक्सर मामला हल्का कर दिया जाता है। यही असमानता कानून के प्रति विश्वास को कमजोर करती है और सामाजिक अन्याय को जन्म देती है। साथियों बात कर हम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थलों का अपमान- विचारधारा से परे राष्ट्रीय क्षति इसको समझने की करें तो, राष्ट्र प्रेरणा स्थल केवल किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा का प्रतीक नहीं होते। वे राष्ट्रीय स्मृति के केंद्र होते हैं,जहाँ से नागरिकों को प्रेरणा, मूल्य और दिशा मिलती है। वहाँ लगी प्रतिमाएँ इतिहास,त्याग और राष्ट्र- निर्माण की गवाह होती हैं। ऐसे स्थानों से गमले चुराना केवल चोरी नहीं,बल्कि राष्ट्रीय चेतना का अपमान है। सार्वजनिक संपत्ति सरकारी नहीं,हमारी है।भारत मेंसार्वजनिक या शासकीय संपत्ति को लेकर एक गहरी गलतफहमी है।लोग इसे सरकारी मानकर उससे दूरी बना लेते हैं या उसे नुकसान पहुँचाना अपना अधिकार समझ लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सरकारी संपत्ति जनता के कर से बनी होती है। हर टूटी सड़क, हर नष्ट किया गया पार्क, हर चोरी किया गया गमला अंततः जनता की जेब से ही दोबारा बनाया जाता है। यह प्रवृत्ति केवल चोरी तक सीमित नहीं है। दंगे, विरोध- प्रदर्शन या आंदोलनों के दौरान सबसे पहले बसें जलाई जाती हैं,सरकारी इमारतें तोड़ी जाती है, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है। यह विडंबना है कि जिन संस्थानों और ढाँचों से आम नागरिक को सबसे अधिक लाभ होता है, वही सबसे पहले निशाने पर आ जाते हैं। साथियों बात अगर हम विरोध का अधिकार बनाम विनाश का अपराध इसको समझने की करें तो,लोकतंत्र में विरोध का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है।परंतु विरोध औरविनाश के बीच एक स्पष्ट रेखा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक शक्ति का प्रतीक है,जबकि सार्वजनिक संपत्ति का विनाश अराजकता का। दुर्भाग्य से, कई बार हम इस अंतर को भूल जाते हैं और अपनी ही संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। मौलिक कर्तव्यों की उपेक्षा संवैधानिक चूक नहीं, नैतिक अपराध है, मौलिक कर्तव्यों को अक्सर अनुसंशात्मक कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है।परंतु किसी भी सभ्य समाज में कर्तव्य केवल कानून से नहीं, नैतिकता से निभाए जाते हैं। जापान, जर्मनी, सिंगापुर जैसे देशों में नागरिक अनुशासन किसी सख्त कानून के कारण नहीं, बल्कि सामाजिक संस्कारों के कारण मजबूत है। साथियों बात अगर हम इस संपूर्ण उपरोक्त चर्चा के दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से समझने तथा नागरिकता की वैश्विक परिभाषा जानने की करें तो, यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तरपर देखें,तो विकसित देशों में सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान एक सामान्य नागरिक गुण माना जाता है। वहाँ पार्क से फूल तोड़ना, सार्वजनिक स्थल को गंदा करना या संपत्ति को नुकसान पहुँचाना सामाजिक अपराध की तरह देखा जाता है। वहाँ नागरिक स्वयं ऐसे व्यवहार को रोकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राष्ट्र की छवि उनके आचरण से बनती है। भारत की वैश्विक छवि और आंतरिक विरोधाभास- भारत आज वैश्विक मंच पर एक उभरती शक्ति है। जी-20, वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, इन सबमें भारत की भूमिका बढ़ी है। परंतु यदि हमारे शहरों में सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित नहीं,स्मारक चोरी का शिकार हैं और नागरिक जिम्मेदारी कमजोर है, तो यह हमारी वैश्विक छवि पर प्रश्नचिह्न लगाता है। साथियों बात कर हम शिक्षा और संस्कार समाधान की पहली सीढ़ी इस दृष्टिकोण से उपरोक्त विषय को समझने की करें तो, इस समस्या का समाधान केवल सख्त कानूनों में नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कारों में छिपा है। स्कूलों और कॉलेजों में नागरिक शास्त्र को केवल परीक्षा का विषय नहीं, बल्कि व्यवहार का हिस्सा बनाना होगा।बच्चों को शुरू से यह सिखाना होगा कि सार्वजनिक संपत्ति उनकी अपनी है।कानून की समानता भरोसे की बहाली का आधार-साथ ही,कानून का समान रूप से लागू होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे चोरी करने वाला गरीब हो या संपन्न,सामान्य नागरिक हो या प्रभावशाली,कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। तभी समाज में न्याय और विश्वास की भावना मजबूत होगी। मीडिया और समाज की भूमिका-मीडिया को भी सनसनी के बजाय आत्ममंथन को बढ़ावा देना होगा।

सम्पादकीय...

उतार-चढ़ाव से भरा रहा 2025

साल 2025 भारतीय राजनीति और वैश्विक कूटनीति के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विजयगाथा के रूप में दर्ज हो गया। यह वर्ष केवल मोदी की चुनावी सफलताओं का नहीं रहा, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच, आर्थिक मजबूती, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के विस्तार का भी साक्षी बना। मोदी ने एक बार फिर यह साबित किया कि उनका नेतृत्व केवल सत्ता संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र को दिशा देने, संकट में निर्णय लेने और दुनिया को भारत की ताकत का अहसास कराने का सामर्थ्य रखता है। 2025 में विभिन्न राज्यों और स्थानीय निकायों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सफलता के पीछे नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति और नेतृत्व की स्पष्ट छाप दिखाई दी। मोदी ने जहां एक ओर सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद को केंद्रीय मुद्दा बनाए रखा, वहीं दूसरी ओर संगठनात्मक मजबूती पर विशेष ध्यान दिया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने, लाभार्थी वर्ग से सीधा संवाद स्थापित करने और विपक्ष की कमजोरियों को उजागर करने की उनकी रणनीति ने भाजपा को बढ़त दिलाई। एनडीए के भीतर मतभेदों को साधते हुए मोदी ने सहयोगी दलों को एकजुट रखा और नए सहयोगियों को जोड़कर गठबंधन का विस्तार भी किया। उनका नेतृत्व सहयोगियों में विश्वास पैदा करने वाला रहा, जिससे एनडीए एक मजबूत और अनुशासित राजनीतिक परिवार के रूप में सामने आया। इसके अलावा, साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का रुख पूरी तरह स्पष्ट और सख्त रहा। 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों और उनके ठिकानों पर कार्रवाई कर यह संदेश दे दिया कि भारत अब केवल आतंकी घटना की निंदा तक सीमित नहीं रहेगा। यह कार्रवाई न केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया को यह समझाने में सफल रही कि भारत आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर अडिग है। मोदी के इस साहसिक निर्णय ने देशवासियों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत किया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि एक निर्णायक शक्ति के रूप में और सुदृढ़ हुई। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ और दबावों के बावजूद मोदी ने भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया। रूस के साथ ऐतिहासिक मित्रता को कायम रखते हुए भारत ने ऊर्जा, रक्षा और कूटनीति के क्षेत्रों में संतुलित नीति अपनाई। मोदी का स्पष्ट संदेश रहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी भी बाहरी दबाव को हावी नहीं होने देगा। रूस के साथ संबंधों को मजबूत रखना और साथ ही अमेरिका तथा यूरोप के साथ भी संतुलन बनाए रखना मोदी की बहुपक्षीय कूटनीति का उदाहरण है। इसके अलावा, 2025 में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। वैश्विक मंदी और महंगाई के दौर में भी भारत ने स्थिरता और विकास दोनों को साधा। मोदी सरकार की नीतियों के चलते महंगाई नियंत्रण में रही, ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम बनी रहीं और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की नीतियों ने रोजगार सृजन और विकास को गति दी। 'जीएसटी उत्सव' के माध्यम से मोदी सरकार ने कर सुधारों की सफलता को जन-जन तक पहुंचाया। जीएसटी ने न केवल कर प्रणाली को सरल बनाया, बल्कि राज्यों की आय बढ़ाने और व्यापार सुगमता में भी अहम भूमिका निभाई। 2025 में जीएसटी संग्रह के नए रिकॉर्ड बने, जिसने सरकार को विकास योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराए और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को और बुलंद किया। ग्लोबल साउथ के मुद्दों को विश्व पटल पर मजबूती से उठाते हुए उन्होंने विकासशील देशों की समस्याओं, जलवायु न्याय और समावेशी विकास की वकालत की। उनकी चीन यात्रा ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा और यह संकेत दिया कि भारत संवाद के साथ-साथ अपने हितों की रक्षा करना भी जानता है। वहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिल्ली आमंत्रित कर मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत वैश्विक शक्ति संतुलन में स्वतंत्र और प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा, 2025 में मोदी ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी वैश्विक स्तर पर मजबूती दी। धार्मिक स्थलों के विकास के जरिये स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ही सांस्कृतिक आयोजनों और योग व आयुष के प्रचार ने भारत की सॉफ्ट पावर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके अलावा, विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना हो या प्राकृतिक आपदाओं में अन्य देशों की मदद करना हो, मोदी सरकार ने हर संकट में तत्परता दिखाई। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार और संवेदनशील वैश्विक शक्ति के रूप में उभरी। बहरहाल, साल 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बहुआयामी विजयगाथा के प्रतीक बनकर सामने आया। चुनावी सफलता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और वैश्विक नेतृत्व जैसे मोर्चों पर मोदी ने अपने निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व की छाप छोड़ी। यह वर्ष न केवल उनके राजनीतिक कद को और ऊंचा कर गया, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और सामर्थ्य की कहानी भी दुनिया के सामने रख गया।

जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से जूझता देश

दुनिया के अमीर देश हों या गरीब, जलवायु परिवर्तन से आने वाली आपदा से कोई नहीं बचा है। भारत में भी पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का असर अब गहराई से अनुभव किया जाने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा देश के तमाम छोटे-बड़े शहर पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से कराह रहे हैं। बढ़ता प्रदूषण संकट आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर आने वाली दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का 450 के आसपास बना रहना, निश्चय ही खतरे की घंटी है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस संकट की जड़ में मानव-जनित जलवायु परिवर्तन है। 1990 के दशक की शुरुआत से भारत का औसत तापमान 0.89 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। प्रदूषण के साथ अब जलवायु परिवर्तन का असर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। इस साल ठंड ने उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत को भी अपनी चपेट में लिया है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्यों- तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना और केरल को समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए जाना जाता है, जहां शीत लहर की स्थिति दुर्लभ होती है। हाल के वर्षों में ठंड के मौसम में उत्तरी हवाओं के असामान्य रूप से गहरे प्रवेश के कारण इन क्षेत्रों के आंतरिक हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। केरल के मुन्नार में तापमान गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
यह केरल में इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान शून्य से भी नीचे जा सकता है। मुन्नार के तापमान ने लोगों को हैरत में इसलिए डाला है क्योंकि केरल का औसत तापमान दिसंबर में 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। दिसंबर के महीने में यहां औसत अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। केरल के अलावा दक्षिण भारत में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, चेन्नई के अलावा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मौसम परिवर्तन का असर देखा जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट और पत्रिका डाउन टू अर्थ के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 334 में से 331 दिन ऐसे रहे, जब देश के किसी ना किसी हिस्से में अत्यधिक मौसमीय घटना दर्ज की गई। यानी पूरे साल का लगभग 99 प्रतिशत समय। अगर 2024 से तुलना करें तो पिछले साल यह आंकड़ा 295 दिनों का था। इन आपदाओं में 4400 से अधिक लोगों की जान गई और करीब 1.74 करोड़ हैक्टेयर फसल बर्बाद हो गई जो बदलते जलवायु संकट की भयावह तस्वीर पेश करती है। मानसून बाढ़ से 2707 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 608 मौतें, जबकि मध्य प्रदेश में 537 लोगों की जान गई। प्री-मॉनसून महीनों में ही 990 मौतें हुईं, जो 2022 की तुलना में लगभग 3 गुना थीं। अगस्त में आई बाढ़ के बाद पंजाब के कई जिलों में खेत पूरी तरह तबाह हो गए। भारत दुनिया के उन दस देशों में शामिल है जो बीते तीन दशकों में जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवॉच की नई रिपोर्ट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के मुताबिक, 1995 से 2024 के बीच भारत में करीब 4.30 मौकों पर प्राकृतिक रूप से असहनीय मौसम की घटनाओं ने 80 हजार से अधिक लोगों की जान ली और 1.3 अरब से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। इन आपदाओं से भारत को लगभग 170 अरब डॉलर (करीब 14 लाख करोड़ रुपए) का आर्थिक नुकसान हुआ है। यह रिपोर्ट ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित कॉप 30 सम्मेलन में जारी की गई। इसमें कहा गया कि भारत में लगातार बढ़ती बाढ़, चक्रवात, सूखा और भीषण गर्मी जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के गंभीर असर को रेखांकित करती हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की स्थिति लगातार खतरे जैसी है, यानी ये घटनाएं अब अलग-अलग नहीं, बल्कि बार-बार दोहराई जा रही हैं। इससे विकास की उपलब्धियों पर असर पड़ रहा है और करोड़ों लोगों की आजीविका खतरे में है। भारत की विशाल जनसंख्या और मानसूनी पैटर्न पर निर्भरता इसे खासतौर पर संवेदनशील बनाती है। रिपोर्ट बताती है कि हर साल करोड़ों लोग किसी न किसी रूप में भीषण मौसम की चपेट में आते हैं। साल 2024 में अकेले भारी मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ों ने गुजरात, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में करीब 80 लाख लोगों को प्रभावित किया। पिछले वर्ष दुनियाभर में सबसे ज्यादा नुकसान बाढ़ और तूफानों से हुआ, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यदि जलवायु परिवर्तन से निपटने की रफ्तार सुस्त रही तो वर्ष 2100 तक दुनिया का तापमान लगभग 2.6 से 2.8 डिग्री तक बढ़ सकता है लेकिन अगर नेट जीरो से जुड़े वादे पूरे कर लिए जाएं तो यह 1.9 डिग्री तक गिर सकता है। इसके तहत सभी देशों को अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को घटना है। भारत में हाल ही के वर्षों में देश में आने वाले चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। बात चाहे तौकते तूफान की करें या अम्फान की। वैश्विक तपन में वृद्धि के कारण तूफान और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। जलवायु परिवर्तन पर सरकार की ओर से कुछ साल पहले एक कार्य योजना तैयार कराई गई थी। उसमें चिंता जताई गई थी कि वर्ष 2021 से 2050 के दौरान समुद्री तापमान में 1.8 से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। जलवायु-संबंधी आपदाओं का संचयी प्रभाव गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है तथा भारत के विकास पथ को खतरे में डाल रहा है। जलवायु जोखिम सूचकांक- 2025 ने वर्ष 1993 से वर्ष 2022 तक भारत को वैश्विक स्तर पर छठा सबसे अधिक प्रभावित देश बताया, जहां नुकसान 180 अरब डॉलर से अधिक था। हालिया शोध बताते हैं कि जलवायु संकट के कारण वर्ष 2100 तक देश को राष्ट्रीय आय का 6.4 से 10 फीसदी से अधिक का नुकसान हो सकता है जिससे 5 करोड़ और लोग फिर से गरीबी में धंस जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, ग्लोबल स्टॉकटेक, के अनुसार तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित रखने के लिए जितने कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती की जरूरत है, वर्ष 2030 तक उसकी तुलना में वायुमंडल में इस गैस का उत्सर्जन 22 अरब टन अधिक होगा। जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के लिए दुनियाभर की सरकारों को त्वरित प्रभावी कार्रवाई करनी होगी, पर पूरी दुनिया इस समस्या के प्रति उदासीन और लापरवाह है।

चांदी जैसा रंग है तेरा!

इन दिनों मेरे लबों पर बार-बार पाकिस्तानी शायर कतील शिफाई की गजल तैरती रहती है-चांदी जैसा रंग है तेरा! शायर ने चांदी के सौंदर्य को शब्दों में ऐसा ढाला और पंकज उधास ने ऐसा गाया कि हर किसी का गुनगुनाना लाजिमी हो गया। चलिए, आज इसी चांदी पर बात करते हैं। चांदी का वैज्ञानिक महत्व तो है ही, भारतीय परंपरा में चांदी को शुभ्रता, समृद्धि, सौम्यता, शांति और ईश्वरीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. देवाधिदेव महादेव ने भी अपने मुकुट पर चांद के रूप में चांदी धारण कर रखी है। भगवान की मूर्तियां चांदी में गढ़ी जाती हैं। चांदी की प्लेट पर न जाने कितने ग्रंथों को उकेरा गया है। हमारे संत चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं। हमें किसी को सम्मान देना रहता है तो चांदी की थाली में खाना खिलाते हैं। बच्चों को पहला निवाला चांदी की चम्मच में खिलाने की परंपरा है। समृद्धि को लेकर एक मुहावरा भी है- चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना। चांदी की शक्ति को लेकर भी एक कहावत बहुत प्रचलित है- पास में चांदी का जूता हो या फिर चवर हो, इसीलिए कवि और शायर चांदी और चांद को लेकर सौंदर्य के प्रतिमान गढ़ते रहे हैं। कतील शिफाई ने लिखा-चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल/ इक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। लेकिन क्या ये लिखते वक्त कतील ने ये सोचा होगा कि चांदी किसी दिन इतनी कातिल भी हो जाएगी? शायर ने लिखा- हर आंगन में आए तेरे उजले रूप की धूप/छैल-छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल! और मजा देखिए कि इस गोरी ने घूंघट ऐसा निकाला कि दुनिया कह उठी-बाप रे चांदी ! और अगली पंक्ति पर गौर करिए- सामने तू आए तो धड़कें मिल कर लाखों दिल/अब जाना धरती पर कैसे आते हैं भौंचाल! तो, इन दिनों चांदी को लेकर दुनिया में भूचाल ही तो मचा है। किसने सोचा था कि साल 2000 में जो चांदी 7900 रुपए प्रति किलो थी, वह 2025 में तीस गुना से ज्यादा भाव खा रही होगी। चांदी का मौजूदा हाल शायर की एक और पंक्ति पर दाद देने को मजबूर कर रहा है- बीच में रंग-महल है तेरा खाई चारों ओर/हम से मिलने की अब गोरी तू ही राह निकाल ! मगर क्या कहें-हमारे आपके जैसे उसके प्रेमी उसके भाव खाने की अदा में ही उलझे जा रहे हैं। चलिए, गजल की अंतिम पंक्ति को भी याद कर लेते हैं-ये दुनिया है खुद-गरजों की लेकिन यार 'कतील'/तूने हमारा साथ दिया तो जिए हजारों साल! इसीलिए तो बड़े-बुजुर्ग एक कहावत भी रच गए हैं-चांदी काटना! यानी बड़ी शान के साथ और मस्ती में रहना। बहरहाल सवाल है कि चांदी क्यों इतना भाव खा रही है? क्यों सोने से भी ज्यादा उछल रही है? बिल्कुल सामान्य भाषा में बताएं तो तकनीकी उन्नति के साथ इसकी मांग बेतहाशा बढ़ती जा रही है।
इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सोलर पैनल के निर्माण से लेकर डिफेंस तक में इसकी खूब खपत हो रही है। चीन इसमें सबसे आगे है। चीन ने 2022 में केवल सोलर उद्योग में ही 4000 टन चांदी की खपत की। सोचिए, मौजूदा खपत क्या होगी? चीन के पास करीब 70 हजार मीट्रिक टन चांदी का भंडार है। हर साल 3300 मीट्रिक टन से ज्यादा उत्पादन करता है। 6000 मीट्रिक टन सालाना उत्पादन के साथ मैक्सिको पहले नंबर पर है। जहां तक भारत का सवाल है तो 2024 में चांदी का वैश्विक उत्पादन 25000 मीट्रिक टन था, जबकि भारत में उत्पादन 700 मीट्रिक टन था।

अतीत से सबक, आगत से उम्मीद

बीजेपी ने राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत यहीं के सी पी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा चुकी है। अगर बीजेपी राज्य में अन्नाद्रमुक के साथ अहम उपस्थिति बनाने में सफल रहती है तो वह राष्ट्रीय स्तर पर कह सकती है कि आने वाले दिनों में राज्य में भी वह मजबूत संख्याबल हासिल कर सकती है। केरल और तमिलनाडु में गंभीर उपस्थिति दक्षिण के प्रश्न प्रदेश को हल करने का मजबूत जरिया बनेगी। लेकिन अगर डीएमके मोर्चा जीतता है तो तय है कि हिंदुत्व विरोधी आक्रामक बयानबाजी का केंद्र दक्षिण बना रहेगा। इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अगर असम में बीजेपी अपनी उपस्थिति बनाए रखती है, बंगाल के किले पर फतह कर लेती है और तमिलनाडु और केरल में अहम उपस्थिति बना लेती है तो माना जाएगा कि उसका राजनीतिक अश्वमेध का घोड़ा दौड़ता रहेगा, लेकिन अगर वह ऐसे नतीजे लाने में नाकाम रही तो उसकी भावी राजनीति भी प्रभावित होगी। इससे कांग्रेसी खेमा नए उत्साह में होगा।

समय का पहिया चलता रहता है। समय के चाक पर हर आगत पल वर्तमान बनता है और फिर अतीत के गोद में समा जाता है। जाते-जाते वह अपनी छाप ही नहीं छोड़ता, कुछ सीख भी दे जाता है। अतीत से प्राप्त अनुभव और सीख की कसौटी पर वह वर्तमान को कसता है और चाहता है कि आने वाला पल अतीत की तुलना में बेहतर गुजरे। मनुष्य की चाहत ऐसी ही होती है। वक्त के पहिये पर सब मनमुताबिक ही घटे-चले तो फिर जीवन चक्र का रोमांच ही खत्म हो जाए। फिर भी मानव की फितरत है, वह आगत को अपने हिसाब से ही घटित होते देखना और भोगना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? अतीत की घटनाएं और भविष्य के नतीजे आने वाले दिनों पर अपना असर जरूर डालते हैं। इसी वजह से राजनीति हर बार आने वाली घटनाओं के प्रति कुछ ज्यादा ही सचेत रहने की कोशिश करती है, उसे अपने हिसाब से घटित करने का प्रयास करते रहती है। महज दो दिनों बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर के पन्ने नए हो जाएंगे। इस नए साल में भी राजनीति चुनावी रणनीति बनाने और उन चुनावों से अपने मनमुताबिक नतीजे हासिल करने की कोशिश में जुटी रहेगी। इस नए यानी साल 2026 में देश के प्रमुख पांच राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों की आहट से राजनीति की दुनिया की पेशानियों पर बल पड़ने लगे हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। इसकी वजह है कि इन राज्यों के चुनाव नतीजे तय करेंगे कि आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा क्या होगी? इनके नतीजे ही तय करेंगे कि आने वाले दिनों में कमल खिलता रहेगा या हाथ को भारत का साथ मिलेगा। इन नतीजों पर ही निर्भर करेगा कि भारत का भावी नेतृत्व कैसा होगा. यूं तो हर राज्य के विधानसभा चुनाव अपने आप में अहम् होते हैं, लेकिन साल 2026 में होने वाले चुनाव बेहद खास होने जा रहे हैं। असम में विगत दो बार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां की 126 सीटों में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 75 सीटें जीती थीं। जिनमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 60 सीटें गई थीं, वहीं उसकी सहयोगी असम गणपरिषद को नौ और अन्य सहयोगी दलों को छह सीटें मिली थीं। जबकि कांग्रेस की अगुआई वाले गठबंधन को 50 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस ने यहां की जिम्मेदारी अपने तेजतर्रार नेता गौरव गोगोई को दी है। जबकि बीजेपी की अगुआई मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के हाथ है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद राज्य की मतदाता सूची से 10.56 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। कांग्रेस की पूरी कोशिश बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनने की है तो बीजेपी की कोशिश उत्तर पूर्व के इस सबसे बड़े राज्य में अपने झंडे को गाड़े रखना है। अगर बीजेपी बनी रही तो उत्तर पूर्व के बहाने उसका राष्ट्रवादी सोच का कारवां बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर कांग्रेस सेंध लगाने में सफल रही तो उससे इलाके में कांग्रेसी आधार को जुटाने को बल मिलेगा। असम से सटे पश्चिम बंगाल में भी असम की तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गर्म है। राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में 294 सदस्यीय विधानसभा में 213 सीटों पर जीत हासिल करके ममता बनर्जी ने सनसनी फैला दी थी, जबकि सत्ता की दावेदार मानी जा रही बीजेपी को महज 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इस बार एसआईआर के चलते राज्य के 7.66 करोड़ मतदाताओं में से 56 लाख के नाम हटाए जा चुके हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग को करीब 20 लाख मतदाता अब भी संदिग्ध लग रहे हैं। आयोग के लिहाज से ये मतदाता पहली बार पंजीकृत हुए हैं और इनकी उम्र पैंतालिस साल और उससे ज्यादा है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाता अगर राज्य के हैं तो वे अब तक कहां थे और उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं डलवाया था और अगर राज्य से बाहर थे तो अचानक ही वे यहां क्यों लौट आए। जाहिर है कि इन नए वोटरों और हटाए गए नाम वाले वोटरों की संख्या को लेकर संदेह की स्थिति है।
इसे लेकर ममता की तृणमूल कांग्रेस पार्टी जहां आक्रामक है, वहीं बीजेपी नए जुड़े करीब 20 लाख संदिग्ध वोटरों को लेकर जवाबी तौर पर हमलावर है। बहरहाल यह तय है कि इन मुद्दों पर ही राज्य के भावी विधानसभा नतीजे तय होंगे। ऐसे में अगर ममता अपना किला बचाए रखती हैं तो तय है कि बीजेपी के पूर्ववर्ती जनसंघ के संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी के गृहराज्य में भगवा झंडा फहराने का उसका सपना अधूरा रहेगा। फिर ममता के पास तर्क होगा कि आने वाले दिनों में वे ही बीजेपी को केंद्रीय स्तर पर चुनौती दे सकती हैं। अगर नतीजे इसके उलट रहे तो बीजेपी कह सकती है कि आने वाले दिनों में उसके सामने कोई चुनौती नहीं रहने वाली। एक दौर में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल को ख्याति वामपंथ के गढ़ के रूप में रही है। लेकिन विगत दो चुनावों से यहां वामपंथी किला बचा हुआ है। इसे उलटबांसी ही कहेंगे कि केंद्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा केरल का वामपंथ कांग्रेस के साथ है। लेकिन राज्य में उसकी लड़ाई कांग्रेस के ही साथ है। वैसे इसी दिसंबर में हुए नगर निकाय चुनावों में बीजेपी ने राज्य की राजधानी तिरुअनंतपुरम् पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वाधिक सक्रियता वाले राज्यों में शुमार होने के बावजूद केरल अब भी बीजेपी के लिए प्रश्न प्रदेश बना हुआ है। इस बार भी माना जा रहा है कि लड़ाई वाममोर्चे और कांग्रेस की अगुआई वाले मोर्चे के ही बीच रहेगी। बीजेपी की कोशिश इस चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाने की ही रहेगी। अगर वह ऐसा करने में सफल रहती है तो सही मायने में अखिल भारतीय पार्टी बनने का वह दावा कर सकती है। अगर वामपंथ यहां से इस बार सत्ता से दूर होता है तो उसकी वापसी की संभावना क्षीण होगी।
उसके लिए खतरा यह होगा कि विपक्षी भूमिका में बीजेपी खुद को उभारने की कोशिश करेगी और वह वामपंथ को धीरे-धीरे उसी तरह गायब कर देगी, जैसे उसने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में कर दिया है। अगर कांग्रेस की अगुआई वाले मोर्चे को जीत मिलती है तो उससे पार्टी का मनोबल बढ़ सकता है। तब बीजेपी विरोधी उसकी केंद्रीय भूमिका को नयी ताकत मिल सकती है। केरल की ही तरह पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में भी बीजेपी तीसरा कोना बनने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। राज्य की 234 सीटों वाली विधानसभा में पिछली बार द्रविड़ मुनेत्र कषगम् यानी डीएमके वाले मोर्चे को 133 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार बीजेपी विपक्षी अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन में उतर कर डीएमके के मोर्चे को पटखनी देने की कोशिश में है। बीजेपी ने राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत यहीं के सी पी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा चुकी है। अगर बीजेपी राज्य में अन्नाद्रमुक के साथ अहम उपस्थिति बनाने में सफल रहती है तो वह राष्ट्रीय स्तर पर कह सकती है कि आने वाले दिनों में राज्य में भी वह मजबूत संख्याबल हासिल कर सकती है। केरल और तमिलनाडु में गंभीर उपस्थिति दक्षिण के प्रश्न प्रदेश को हल करने का मजबूत जरिया बनेगी। लेकिन अगर डीएमके मोर्चा जीतता है तो तय है कि हिंदुत्व विरोधी आक्रामक बयानबाजी का केंद्र दक्षिण बना रहेगा। इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अगर असम में बीजेपी अपनी उपस्थिति बनाए रखती है, बंगाल के किले पर फतह कर लेती है और तमिलनाडु और केरल में अहम उपस्थिति बना लेती है तो माना जाएगा कि उसका राजनीतिक अश्वमेध का घोड़ा दौड़ता रहेगा, लेकिन अगर वह ऐसे नतीजे लाने में नाकाम रही तो उसकी भावी राजनीति भी प्रभावित होगी। इससे कांग्रेसी खेमा नए उत्साह में होगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कल्पना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पश्चिमबाद एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/39862)

सपा की बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा

मुरादाबाद।

मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड महानगर मुरादाबाद की एक बैठक यूथ बिग्रेड के महानगर केम्प कार्यालय पर मंगलवार को आयोजित हुई। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान कई युवाओं ने सपा का दामन थामा। मुख्यातिथि समाजवादी पार्टी जिला प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नौजवान ही सपा के वफादार कार्यकर्ता हैं और यही भविष्य के नेता। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमेशा नौजवानों को सम्मान दिया। आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यूपी में जब-जब सपा की सरकार बनती है, नौजवानों के हित सर्वोपरि होते हैं। लिहाजा युवाओं को भी आगामी चुनाव के लिए अभी से कमर कस लेना चाहिए। गांव-गांव जाकर गरीबों नौजवानों की समस्याओं को अपने अपने स्तर से हल कराएं। बेईमान सरकार के जनविरोधी कारनामो को जनता के सामने उजागर करें। मुलायम सिंह यूथ बिग्रेड के महानगर अध्यक्ष रजिउद्दीन खान ने कहा हम सभी युवाओं और आपको समाजवादी पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारी पार्टी में शामिल होकर आप समाज में सामाजिक न्याय और समृद्धि की दिशा में योगदान करने का मौका पाएंगे। हमारे साथ जुड़कर, आप अपने विचारों को साझा करने और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रयासों में शामिल हो सकते हैं।बैठक महानगर मुलायम सिंह यूथ बिग्रेड की कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया नए पदाधिकारियों को मनोयन पत्र भी दिए गए।बैठक में वरिष्ठ नेता लुकमान ख़ान, फैज़ी ख़ान, मीम फ़ैसल, शानू अली, मो. रेहान, सचिन श्रीवास्तव, हर्ष यादव, राहुल कुमार, दानिश ख़ान, ज़की ख़ान, समीर अहमद, राशिद अली, मोहन यादव मो. इमरान, मो सलमान,रामवीर यादव मो अज़ीम, मो राशिद, मौ अदनान, ओरंगजेब, संजीव प्रभाकर आदि मौजूद थे।

कुन्दरकी विधायक ने लखनऊ में उठाये विकास संबंधी मुद्दें

मुरादाबाद।

लखनऊ में दूसरे दिन प्रतिनिहित विधायन समिति की जल शक्ति एवं गृह विभाग से सम्बंधित बैठक सभापति राजीव सिंह उर्फ़ बब्बू भैया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कुंदरकी विधानसभा में जल शक्ति एवं गृह विभाग से सम्बंधित समस्याओं को उठाते हुए कहा कि मुरादाबाद में डियर पार्क रामनगर मझरा से मिलक अका डिलारी, चमरौआ, मुंडिया मलूकपुर, मुंडिया घोसियान, भीतखेड़ा, जैतपुर विशाह्ट से मानपुर पट्टी होते हुए आगापुर नेशनल हाईवे रामपुर तक स्टेट हाईवे निर्माण कार्य (राजेड़ा नदी व कोसी नदी पर पुल निर्माण सहित) अनुमानित लम्बाई 38 किमी को जल्दी शुरू करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करें साथ ही मेरी विधानसभा में रामगंगा नदी/कोसी नदी में बाढ एवं भारी बर्षा के कारण अनेक ग्रामों जैतुपर विशाह्ट, चन्दनपुर ,वीरपुर वरियार उर्फ खरक, घोसीपुरा आदि में कटान का भय बना रहता है जिसके कारण उक्त नदियों के किनारे पर बसे ग्रामों में पिचिंग कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक है इसको भी जल्दी प्रारम्भ कराया जाये। विधायक कुंदरकी ने गृह विभाग से सम्बंधित समस्याओं को भी बैठक में उठाते हुए बताया की जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में कार्यरत चौकीदारों में से कुछ की मृत्यु हो चुकी है परन्तु उनके आश्रितों द्वारा उनके वारिश के रुप में नियुक्ति हेतु आवेदित पत्रावली पुलिस विभाग में लम्बित हैं किन्तु इनको अभी तक मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति नहीं मिल पायी है जिससे इन लोगों को जीवन-यापन करने में तथा पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन करने में आर्थिक रुप से कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है साथ ही जनपद के विभिन्न शस्त्र धारकों की मृत्यु/आयु अधिक होने के कारण उनके वारिसों के वारिसान के रुप में शस्त्र लाईसेंस नहीं हुए हैं जबकि इनकी पत्रावली सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण कर सम्बन्धित कार्यालय में काफी समय से लम्बित पडी हुई हैं। समिति के माध्यम से सम्बन्धित को निर्देशित कराते हुए उक्त लम्बित वारिसान शस्त्र लाईसेंस अति शीघ्र जारी कराये और चौकीदारों की नियुक्ति भी शीघ्र की जाये। बैठक में प्रतिनिहित विधायन समिति के सभी सदस्य एवं जल शक्ति एवं गृह विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

गलन और सर्दी के बीच प्रदेश में होगी बारिश की एंट्री

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में हो रही ठंड और कोहरे के प्रकोप के बीच विक्षोभ के असर से पहली जनवरी को पश्चिमी यूपी के तराई हिस्सों में बारिश की भी संभावना है।मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार से यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तात्कालिक तौर पर पारे का गिरना थमेगा। पूर्वानुमान है कि यूपी में अगले चार दिनों में दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़त आएगी। वहीं इस विक्षोभ के असर से पहली जनवरी को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी के 17 जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी के संकेत हैं। बुधवार के लिए प्रदेश के 37 जिलों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही 17 जिलों में दिन के तापमान में भारी गिरावट यानी शीत दिवस की चेतावनी जारी किया गया है।

7 जनवरी को होगी महत्वपूर्ण बैठक, डीएम ने अधिकारियों को किया अलर्ट

मुरादाबाद।

सभापति कुंवर महराज सिंह के सभापतित्व में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जांच किए जाने के संबंध में गठित समिति द्वारा 7 जनवरी 2026 को जनपद के संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित होगी।

जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में इस संबंध में आयोजित बैठक के दौरान समिति के भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत विभागों के स्तर से तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने नगर निगम, आवास विकास, जिला पंचायत एवं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के साथ ही अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि वे निर्धारित बिंदुओं पर त्रुटिरहित जानकारी तैयार करके समिति के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान समिति के सभापति और सदस्यों द्वारा जिन विभागों के बारे में जानकारी ली जाएगी उन विभागों के अधिकारियों द्वारा समिति के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभागीय जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया जाए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी और एडीएम प्रशासन श्रीमती संगीता गौतम के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण मौजूद रहे।

पाककला एवं बेकरी में एक माह के लिए मिलेगा प्रशिक्षण

मुरादाबाद। जिले में मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पाककला एवं बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र सुरेन्द्र कुमार जायसवाल ने बताया कि एक माह के लिए आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभाग द्वारा प्रशिक्षण के लिए ×0 सीटें निर्धारित हैं। चयनित प्रतिभागियों को विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से साउथ इंडियन, चाइनीज फास्ट फूड समेत अन्य विभिन्न भारतीय एवं कॉन्टिनेंटल फूड तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए प्रतिभागियों को निःशुल्क प्रशिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि एक माह के इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सूक्ष्म/लघु उद्योग लगाने के इच्छुक प्रतिभागियों के नियमानुसार प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 01 लाख रुपए तक सब्सिडी भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए निर्धारित योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी का साक्षर होना अनिवार्य है, आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा प्रशिक्षण सत्र में प्रवेश के लिए अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में मेरिट अथवा लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रवेश फार्म प्राप्त करने एवं जमा करने के लिए अंतिम तिथि 09 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है साथ ही प्रशिक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र जिला पंचायत परिसर मुरादाबाद में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

सपा नेता व पूर्व मंत्री के बेटे पर फायरिंग, चचेरे भाई ने ही किया कातिलाना हमला; जाते-जाते दे गया बड़ी धमकी

गुलरिहा । यूपी के गोरखपुर स्थित गुलरिहा थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व मंत्री के बेटे पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी गई। गनीमत रही कि गोली पास से गुजर गई और पीड़ित बाल-बाल बच गया। घटना को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। मामला आपसी और पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, खुटहन खास निवासी अमरेंद्र निषाद पूर्व मंत्री जमुना निषाद व पूर्व विधायक राजमती निषाद के बेटे हैं। अमरेंद्र निषाद ने गुलरिहा पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि मंगलवार को करीब 2:30 बजे वह अपने घर पर खेती-बारी से जुड़े कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान उनका चचेरा भाई, जो कि पूर्व मंत्री बताए जा रहे हैं, उन्हें अपनी गाड़ी के पास बुलाया। आरोप है कि वहां पहले से चल रहे आपसी विवाद के चलते चचेरे भाई ने जान से मारने की नीयत से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोली अमरेंद्र निषाद के बेहद करीब से गुजर गई, जिससे वह बाल-बाल बच गए। पीड़ित का कहना है कि फायरिंग के बाद आरोपी ने उन्हें धमकी दी कि इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। घटना के बाद घबराए अमरेंद्र निषाद ने तत्काल गुलरिहा पुलिस को फोन कर सूचना दी। इसके बाद वह अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंचे और पूरे मामले की लिखित तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गुलरिहा थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

रेल यात्रियों को नहीं मिल रहा गुणवत्तायुक्त एवं सुरक्षित खान-पानः डॉ. पवन जैन

डीआरयूसीसी की बैठक में उठाई मुरादाबाद मंडल की रेल समस्याएँ

मुरादाबाद।

डीआरएम कार्यालय स्थित मनन हाल में डी आर एम संग्रह सिंह मौर्य की अध्यक्षता में संपन्न डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी (डीआरयूसीसी) की बैठक में सदस्य डॉ. पवन कुमार जैन ने मुरादाबाद रेलवे मंडल से जुड़ी अनेक लंबित समस्याओं एवं यात्री हित से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के कारण आम नागरिकों एवं दैनिक रेल यात्रियों को लगातार असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिनका शीघ्र समाधान जनहित में अत्यंत आवश्यक है।

डॉ. जैन ने बैठक में कपूर कंपनी पुल के निर्माण पर रेलवे प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान पुल पुराने पुल की तुलना में संकरा है, जबकि यातायात दबाव को देखते हुए इसे अधिक चौड़ा बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने इस विषय पर पुनर्विचार का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद एक प्रमुख रेलवे मंडल मुख्यालय होने के बावजूद यहां से किसी भी लंबी दूरी की ट्रेन का संचालन प्रारंभ नहीं होता, जिसे वॉशिंग लाइन के अभाव से जोड़ा जाता है। यह विषय पूर्व में भी कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। डॉ. जैन ने यह भी कहा कि मुरादाबाद जैसे बड़े जंक्शन पर आईआरसीटीसी कैंटीन की अनुपलब्धता के कारण यात्रियों को गुणवत्तायुक्त एवं सुरक्षित खान-पान नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही की मांग की। बैठक में उन्होंने मुरादाबाद-रामपुर-बरेली मार्ग पर सीधी पैसेंजर ट्रेन चलाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान में यात्रियों को चंदौसी होकर अनावश्यक रूप से लंबा रास्ता तय करना पड़ता है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मुरादाबाद मंडल के 19 रेलवे स्टेशनों के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने बिजनौर स्टेशन का कार्य पूर्ण होने और धमपुर स्टेशन का कार्य लगभग पूरा होने पर रेलवे टीम की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित स्टेशनों पर उस स्तर की ट्रेनों का संचालन नहीं होने से जनता को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होने शेष स्टेशनों की प्रगति रिपोर्ट भी साझा करने की मांग की। अंत में डॉ. पवन जैन ने कहा कि ये सभी विषय सीधे तौर पर जनहित, यात्री सुविधा और रेलवे की छवि से जुड़े हुए हैं। उन्होंने रेलवे प्रशासन से इन समस्याओं पर शीघ्र एवं ठोस कार्यवाही कर मुरादाबाद मंडल की रेल सेवाओं को अधिक सुरक्षित, सुदृढ़ और यात्रीहितकारी बनाने का अनुरोध किया।

दिल्ली-एनसीआर में कोहरे का सितम, 500 मीटर विजिबिलिटी; फ्लाइट्स से ट्रेनों तक पर दिखा असर

नई दिल्ली । दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठंड और घने कोहरे का सितम जारी है। साथ ही वायु प्रदूषण की मार भी दिल्लीवालों को झेलनी पड़ रही है। आज सुबह भी घने कोहरे की मोटी चादर ने राजधानी को ढक लिया है। जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। दिल्ली के धौला कुआं, द्वारका एक्सप्रेसवे, कर्तव्य पथ और अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाकों में कोहरा दिखा। मंगलवार सुबह दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 2026 गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल चल रही है। इसके अलावा कोहरे के दौरान ट्रेन की आवाजाही को कम करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में सुबह साढ़े 10 बजे दृश्यता में सुधार देखने को मिला। पालम इलाके में 500 मीटर हल्की धुंध दिखी तो वहीं दूसरी तरफ सफदरजंग में 350 मीटर विजिबिलिटी दर्ज हुई। फरीदाबाद में लगातार तीन दिन से गिर रहे घने कोहरे से यातायात प्रभावित हो रहा है। सामने से कुछ ही मीटर की दूरी पर भी कुछ भी नहीं दे रहा है। जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। दृश्यता बहुत कम होने पर सुबह-सुबह कामकाज व अन्य कार्यों के लिए जा रहे दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कोहरे की वजह से एक बार फिर फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स लेट हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक 60 अराइवल, 58 डिपार्चर कैंसिल हो गए है और 16 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है। पूरे उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है। रविवार रात सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा। कई जगह दृश्यता शून्य तक गिर गई। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते रहे, दिल्ली में ही 600 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं और 100 से अधिक ट्रेनें भी निर्धारित समय से देर से चलीं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा से लेकर पंजाब, झारखंड और बिहार में शीतलहर के चलते लोग ठिठुरते रहे। मौसम विभाग के अनुसार, कुछ जगहों पर मंगलवार को दिन के तापमान में सामान्य से 4-5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में रविवार रात से सोमवार सुबह तक बेहद घना कोहरा रहा। जम्मू में दृश्यता 50 मीटर, हिमाचल के बिलासपुर में 40 मीटर, उत्तराखंड के देहरादून में 50 मीटर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज महल घने कोहरे में छिपा दिखा। आगरा में ताज महल के पास दृश्यता 30 मीटर, मेरठ में 40 मीटर तो हरियाणा के हिसार में 40 मीटर, चंडीगढ़ में 30 मीटर और दिल्ली के पालम और सफदरजंग में 50 मीटर दर्ज की गई। पंजाब के अमृतसर, आदमपुर, हलवारा, पठानकोट और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कई क्षेत्रों में दृश्यता शून्य रही। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की मार भी पड़ रही है। सोमवार शाम चार बजे के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 401 और नोएडा का 410 रहा। गुरुग्राम में एक्यूआई 318, ग्रेटर नोएडा में 356, गाजियाबाद में 393 और मेरठ में 316 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है।

रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत- मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 को बताया नागरिक- केंद्रित सुधारों का महावर्ष

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 2025 को भारत के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया और कहा कि देश ने कराधान, श्रम, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और ग्रामीण रोजगार सहित कई क्षेत्रों में सुधारों के साथ सुधार की एक्सप्रेस में सवार हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने सुधार की रफ्तार पकड़ ली है! 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, जिन्होंने हमारी विकास यात्रा को गति प्रदान की है। ये सुधार एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को भी बल देंगे। एक विस्तृत लिंक्डइन पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सुधारों को एक सतत राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया गया है, जो पिछले 11 वर्षों की प्रगति पर आधारित है। उन्होंने लिखा, हमने संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन को सरल बनाया और दीर्घकालिक, समावेशी विकास की नींव को मजबूत किया। प्रमुख उपायों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में परिवर्तन शामिल थे, जिसमें विवादों को कम करने और अनुपालन में सुधार लाने के लिए 5फीसदी और 18फीसदी की सरल दो-स्तरीय संरचना लागू की गई। मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत मिली क्योंकि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आयकर नहीं देना होगा, जबकि 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को आयकर अधिनियम, 2025 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। लघु और मध्यम व्यवसायों को भी लाभ हुआ क्योंकि लघु कंपनियों की परिभाषा का विस्तार करके इसमें 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली फर्मों को शामिल किया गया, जिससे अनुपालन आसान हुआ और लागत में कमी आई। सरकार ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से बीमा क्षेत्र में 100फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। पूंजी बाजारों में, निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करने, शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाने के लिए प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक पेश किया गया। पांच नए समुद्री कानून पारित किए गए, जिनसे रसद व्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ और लागत में कमी आई।

"प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को भारत के लिए परिवर्तनकारी सुधारों का वर्ष बताया, जिसमें देश को सुधारों की एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार बताया गया है। इन व्यापक सुधारों ने कराधान, श्रम, व्यापार, शिक्षा और ग्रामीण रोजगार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में गति पकड़ी है, जिनका उद्देश्य एक विकसित भारत के निर्माण को गति देना और दीर्घकालिक समावेशी विकास की नींव को मजबूत करना है।

जन विश्वास पहल के तहत, अनावश्यक अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए 71 पुराने कानूनों को निरस्त किया गया। श्रम सुधारों के तहत 29 पुराने कानूनों को चार आधुनिक श्रम संहिताओं में विलय कर दिया गया, जिससे सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हुआ, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हुई और महिला कार्यबल की भागीदारी को प्रोत्साहन मिला। भारत ने न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते किए और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को लागू किया, जिससे बाजार पहुंच और निवेश के अवसरों में वृद्धि हुई। परमाणु ऊर्जा का जिम्मेदारीपूर्वक विस्तार करने, निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और देश की बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शांति अधिनियम पेश किया गया।ग्रामीण रोजगार गारंटी को ग्राम विकास अधिनियम, 2025 के तहत 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है ताकि गांवों के बुनियादी ढांचे और आजीविका को मजबूत किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे कई निकायों के स्थान पर एक एकल उच्च शिक्षा नियामक की योजना बनाई जा रही है, जिससे संस्थागत स्वायत्तता, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सुधारों के पीछे के दर्शन को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये सुधार सहानुभूति के साथ तैयार किए गए हैं, जिनमें छोटे व्यवसायों, युवा पेशेवरों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग की वास्तविकताओं को ध्यान में रखा गया है ये हमारे एक दशक से चले आ रहे उन प्रयासों को गति प्रदान करते हैं जिनके तहत हम नियंत्रण-आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर विश्वास पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें नागरिक को केंद्र में रखा गया है।

सीएम बोलीं- शकुनि का चेला आया

घुसपैठ सिर्फ बंगाल से तो क्या पहलगाम हमला आपने कराया

पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर करारा जवाब दिया, जिन्होंने टीएमसी सरकार की तुलना भय और भ्रष्टाचार से की थी और उन पर सीमा बाड़ लगाने के लिए जमीन देने से इनकार करने का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी ने जवाब में भाजपा नेताओं की तुलना महाभारत महाकाव्य के पौराणिक पात्रों दुर्योधन और दुशासन से की। शाह के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने पेट्रापोल और अंडाल में बाड़ लगाने के लिए जमीन दी थी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि 14 साल पहले की स्थिति याद कीजिए, लोग डरे हुए थे। बांकुड़ा के लिए बहुत विकास कार्य किए गए और जल संकट को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया गया। चुनाव आ गए हैं और एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। टीएमसी नेता ने आगे कहा कि बंगाल में दुशासन आ गया है। चुनाव आते ही दुशासन और दुर्योधन प्रकट होने लगते हैं। यह शकुनी का शिष्य दुशासन है, जो सूचना जुटाने आया है।

आज वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। अगर मैंने जमीन नहीं दी होती तो क्या होता? पेट्रापोल में जमीन किसने दी? अंडाल में जमीन किसने दी? जबकि केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीमा से घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि वे कहते हैं कि प्रवासी केवल बंगाल से आते हैं। अगर ऐसा है, तो क्या आपने पहलगाम में हमला करवाया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था? भ्रष्ट भाजपा पार्टी। वे सर के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। केवल आप और आपका बेटा खाएंगे, और हम उपदेश सुनते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन और प्रवासियों का आगमन गरमागरम मुद्दे बन गए हैं, जिन्हें राज्य में आगामी 2026 विधानसभा चुनावों में मुद्दा बनाया जा सकता है। शाह ने कहा कि त्रिपुरा और असम में घुसपैठ रुक गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह जारी है। शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए घुसपैठ जारी रखना चाहती हैं, जिसका मकसद अपना वोट बैंक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ममता, आज मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। कौन सी सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने से इनकार करती है? मैं खुद इसका जवाब दूंगा।

अल्मोड़ा में यात्रियों की चीखें, खाई में गिरी बस, 7 जानें जाने की आशंका

अल्मोड़ा। मंगलवार सुबह अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण के पास यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के अनुसार, इस हादसे में छह से सात लोगों के मरने की आशंका है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की बचाव टीमों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। घायलों को इलाज के लिए भिकियासैंण के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा, बचाव टीमों को मौके पर भेज दिया गया है। कुछ लोगों के मरने की खबरें हैं।

सीएम धामी ने दुख जताया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जताया है। सीएम धामी ने कहा कि वह जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और घायलों को जरूरी मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, हमें अल्मोड़ा जिले में भिकियासैंण से रामनगर जा रही भिकियासैंण-विनायक मोटर रोड पर एक बस दुर्घटना की बेहद दुखद खबर मिली है, जिसमें यात्रियों की जान गई है। यह घटना बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है। उन्होंने आगे कहा, हादसे में घायल यात्रियों को जिला प्रशासन द्वारा तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए बड़े मेडिकल सेंटरों में रेफर किया गया है। पूरे मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है, और मैं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूं। केंद्रीय मंत्री और अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ के सांसद अजय टम्टा ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और बचाव दल एक बड़े बचाव अभियान में लगे हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टम्टा ने एक्स पर पोस्ट किया, अल्मोड़ा जिले में भिकियासैंण-विनायक मार्ग पर हुए भयानक सड़क हादसे की खबर बेहद दुखद और परेशान करने वाली है। खबरों के मुताबिक, एक बस के सड़क से फिसलकर खाई में गिरने से कई यात्रियों की मौत हो गई या वे घायल हो गए। उन्होंने आगे कहा, घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान में लगी हुई हैं, और घायलों को इलाज के लिए तुरंत मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं।

सीटों पर धोखा : रामदास अठावले बोले- बीजेपी ने किया विश्वासघात, अकेले लड़ेंगे बीएमसी चुनाव

मुंबई।

मुंबई में गठबंधन तोड़ने का एलान

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के प्रमुख रामदास अठावले ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान उनकी पार्टी को दरकिनार करने का आरोप लगाया। मुंबई में आरपीआई की राजनीतिक ताकत पर प्रकाश डालते हुए, अठावले ने कहा कि भाजपा और शिवसेना के पुनर्मिलन ने उनकी पार्टी की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, और कहा कि आरपीआई को सीट बंटवारे की चर्चाओं में शामिल तक नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को बहुत देर से सूचित किया गया कि उसे केवल छह सीटें आवंटित की गई हैं। अठावले ने एएनआई को बताया कि भाजपा और शिवसेना के गठबंधन ने आरपीआई को टिकट देने में समस्या पैदा कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी मुंबई में एक बहुत मजबूत पार्टी है... लेकिन भाजपा ने हमें नजरअंदाज कर दिया है... चर्चाओं के दौरान हमें एक बार भी नहीं बुलाया गया। अगर आरपीआई को भाजपा-शिवसेना की चर्चाओं में बुलाया गया होता, तो हमें कुछ सीटें आवंटित की जा सकती थीं... कल रात 2 बजे हमें बताया गया कि हमें छह सीटें दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरपीआई ने भाजपा को 26 सीटों की सूची सौंपी थी और उसे 14 से 15 सीटों के आवंटन की उम्मीद थी। उन्होंने इस परिणाम को धोखा करार दिया और घोषणा की कि आरपीआई मुंबई में 28 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी और अपने चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करेगी। अठावले ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे संपर्क कर आरपीआई को छह सीटें आवंटित किए जाने की जानकारी दी थी। हालांकि, अठावले ने कहा कि ये सीटें उनकी पार्टी द्वारा अनुरोधित सीटों में शामिल नहीं थीं और आरपीआई के इन निर्वाचन क्षेत्रों में कोई उम्मीदवार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने जो 26 सीटों की सूची दी थी, उनमें से हमें उम्मीद थी कि 14-15 सीटें आरपीआई को मिलेंगी... यह भाजपा का घोर विश्वासघात है। इसीलिए हम मुंबई की 28 सीटों पर आरपीआई के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज मुझे फोन किया और बताया कि उन्होंने आरपीआई को छह सीटें दे दी हैं। लेकिन हमने उनसे कहा कि ये वो सीटें हैं जिनकी हमने मांग नहीं की थी। वहां हमारे उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमारे उम्मीदवार हैं, इसलिए ये आपके उम्मीदवार हैं। चुनाव चिह्न भी आपका ही होगा। मतभेद के बावजूद, आरपीआई प्रमुख ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महायुति गठबंधन को समर्थन देना जारी रखेगी।

आयकर विभाग की लुलु मॉल पर बड़ी कार्रवाई, 27 करोड़ टैक्स न देने पर कंपनी का बैंक खाता फ्रीज

लखनऊ । आयकर विभाग ने लुलु मॉल का बैंक खाता फ्रीज कर दिया है। जानकारी अनुसार, 27 करोड़ रुपये के आयकर का भुगतान न किए जाने पर यह कदम उठाया गया। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान कर देनदारी और लेनदेन से जुड़े कई दस्तावेजों की समीक्षा की गई, जिसमें कर चोरी के संकेत मिले। आयकर विभाग का कहना है कि बकाया कर राशि को लेकर कंपनी को पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन तय समयसीमा में भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद विभाग ने कानून के तहत बैंक खाता फ्रीज करने की कार्रवाई की।

यूपी में फिर बढ़ी एसआईआर की समय सीमा, अब छह जनवरी को आएगी पहली कच्ची सूची

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषित तिथियों में संशोधन करते हुए नई तिथियां जारी कर दी गई है। संशोधित तिथियों के अनुसार, अब मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 6 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक निर्धारित की गई है। 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च, 2026 को किया जाएगा।

अब आरक्षी, मुख्य आरक्षी और जेल वार्डर की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं, कैबिनेट में प्रस्ताव पास

लखनऊ । यूपी पुलिस के आरक्षी, मुख्य आरक्षी और जेल वार्डरों की भर्ती में निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। अभी तक यूपी पुलिस के आरक्षी व मुख्य आरक्षी के साथ जेल वार्डरों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होती थी। निगेटिव मार्किंग खत्म करने का प्रस्ताव कैबिनेट में गया था। प्रस्ताव कैबिनेट में बाई सर्कुलेशन पास किया गया है। अब सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, मुस्लिम दोस्त ने चला दी गोली

ढाका ।

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है. यह मामला उसी मयमनसिंह जिले का है, जहां 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया था और फिर बीच चौराहे पर उसके शव को जला दिया गया था. पिछले दस दिनों में यह तीसरा मामला है, जब बांग्लादेश में हिंदू युवक मारा गया है. इससे पहले ढाका में अमृत मंडल को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उस पर हफ्ता मांगने का आरोप लगाया गया था. सोमवार (29 दिसंबर, 2025) को शाम 6.45 बजे एक फैक्ट्री में यह घटना हुई. लबीब ग्रुप गार्मेंट के भालुका उपजिला इलाका स्थित सुल्तान स्वेटर्स लिमिटेड में यह घटना हुई है, जहां पर बजेंद्र बिस्वास अपने मुस्लिम दोस्त नोमान मिया के साथ था. बजेंद्र की मौत उसकी थाई में गोली लगने की वजह से हुई है, यह गोली नोमान की बंदूक से ही चली थी. पुलिस ने नोमान को गिरफ्तार कर लिया है. बजेंद्र अंसार का सदस्य था. फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए 20 अंसार सदस्यों को तैनात किया गया था. पुलिस और चश्मदीदों के अनुसार बजेंद्र और नोमान सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर फैक्ट्री में तैनात हुए थे और वह फैक्ट्री के अंदर ही अंसार बैरक में रहते थे. बातचीत के दौरान नोमान ने बजेंद्र बिस्वास पर बंदूक तान दी. बताया जा रहा है कि वह मजाक में ऐसा कर रहा था, लेकिन उससे बंदूक का ट्रिगर दब गया और गोली बजेंद्र की लेफ्ट थाई में लग गई.

हरियाणा में निर्भया जैसी हैवानियतः चलती कार में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता को सड़क पर फेंक कर भागे

नई दिल्ली ।

हरियाणा के फरीदाबाद कोतवाली थाना इलाके में 28 साल की महिला को कार में लिफ्ट देकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मां से नाराज होकर घर से निकली महिला को कार सवार दो युवकों ने गंतव्य तक छोड़ने के बहाने कार में बैठाया। आरोप है कि दो घंटे से अधिक समय तक आरोपियों ने महिला को कार में फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर घुमाया। देर रात लगभग 3 बजे महिला को एसजीएम नगर स्थित मुल्ला होटल के पास चलती कार से फेंककर आरोपी कार भगा ले गए। महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सीसीटीवी जांच रही पुलिस

पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि परिवार की शिकायत पर कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर आरोपियों की तलाश में जुटी है।

सहेली के घर जाने की कही बात

पीड़िता महिला फरीदाबाद की ही रहने वाली है। पीड़िता की बहन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोमवार रात लगभग साढ़े 8 बजे उनके पास बहन की कॉल आई थी।

उसे बताया गया कि घर में मां से कहासुनी हो गई है और मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूं। पीड़िता ने कहा था कि सहेली के घर से 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। देर रात लगभग 12 बजे महिला दो नंबर चौक से कल्याणपुरी तीन नंबर चौक तक जाने के लिए सवारी वाहन के इंतजार में थी। इस दौरान एक वैन आकर रुकी जिसमें दो युवक सवार थे। आरोप है कि लिफ्ट देने के बाद दोनों युवक वैन को कल्याणपुरी चौक की बजाय गुरुग्राम रोड की ओर ले जाने लगे।

चलती कार से पीड़िता को फेंका

फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग स्थित हनुमान मंदिर से आगे जाकर एक आरोपी कार चलाता रहा जबकि दूसरे ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। लगभग दो घंटे तक आरोपी वैन को फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर घुमाते रहे। महिला ने विरोध भी किया, लेकिन आरोपियों से बच नहीं सकी। देर रात करीब 3 बजे आरोपियों ने एसजीएम नगर के राजा चौक स्थित मुल्ला होटल के पास महिला को चलती वैन से फेंका और निकल गए। सड़क पर गिरने से महिला के चेहरे व अन्य हिस्सों पर चोट लगी। उसके चेहरे पर टांके लगाए गए हैं।

डॉक्टरों ने किया दिल्ली रेफर

देर रात पीड़िता ने अपनी बहन को कॉल कर इस बारे में बताया। बहन मौके पर पहुंची तो देखा कि पीड़िता बदहवास हालत में थी। उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। बाद में हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर किया, लेकिन परिजनों ने फरीदाबाद के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, कई लोग घायल, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद

गुजरात । अहमदाबाद जिले के साणंद तालुका के कलाना गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में झगड़े के बाद पत्थरबाजी की घटना हुई है. सोमवार (29 दिसंबर) रात को हुए पत्थरबाजी के बाद मंगलवार (30 दिसंबर) सुबह फिर से हालात बिगड़ गए. पुलिस ने गांव में लगे कैमरे का DVR भी जब्त कर लिया. इसके साथ ही पुलिस ने गांव में तलाशी शुरू कर दी है.एसपी और डिप्टी एसपी समेत पुलिस की टीम गांव पहुंची. मिली जानकारी के मुताबिक, साणंद के कलाना गांव में रहने वाले दो गुटों के युवकों के बीच पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट को लेकर विवाद चल रहा है. सोमवार को एक गुट के युवक को दूसरे गुट के युवकों ने यह कहते हुए पीटा कि तुम सामने क्यों देख रहे हो इसके बाद दोनों गुटों के लोग इकट्ठा हो गए और मारपीट करने लगे. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है. आज सुबह फिर से हालात बिगड़ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई. पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कलाना गांव पहुंचकर हालात को काबू में किया. कलाना गांव साणंद GIDC पुलिस स्टेशन एरिया में है. गांव में सुरक्षा को कड़ा किया गया और फिलहाल शांति है. जिन लोगों पर शक है उनसे पूछताछ चल रही है. पुलिसने बताया जो लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वर्चस्व की लड़ाई से यह मामला शुरू हुआ और पथराव तक पहुंच गया.

अब तक 42 लोगों को हिरासत में लिया गया- पुलिस

पुलिस ने बताया कि दो बाइक वाले एक दूसरे के सामने आए, तुमने मेरी तरफ क्यों देखा ईगो टसल (वर्चस्व की लड़ाई) में उनका आपस में झगड़ा हुआ. उस झगड़े का किसी ने वीडियो बना दिया. ये वीडियो दोनों गुटों के ग्रूप्स में पहुंचा और विवाद बढ़ गया. पुलिस ने कहा कि पत्थरबाजी के पांच-सात मिनट बाद ही पुलिस पहुंच गई. अब तक 42 लोगों को हिरासत में लिया गया है.